समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1388 सन् 2024

चन्द्रप्रकाश एम. तिवारी व अन्य ....वादीगण

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ....प्रतिवादीगण

इंडेक्स

क्र. संख्या	विवरण / ब्यौरे	पृष्ट संख्या
01	Additional Affidavit on behalf of the Applicant	
02	Annexure A-1 Copy of the order dated 12.07.2021 IN O.A.165 of 2021	
03	Annexure A-2 Copy of the order dated 25.01.2022 IN O.A.165 of 2021	
04	Annexure A-3 Copy of the order dated 14.09.2022 IN O.A.165 of 2021	
05	Annexure A-4 Copy of the order dated 10.10.2022 IN RA No. 33 of 2022 IN EA No. 02 of 2022 IN O.A.114 of 2021	
06	Annexure A-5 Copy of the order dated 14.12.2022 IN EA No. 38 of 2022 IN O.A.165 of 2021	

दिनांक 10.03.2025

आवेदक

संतोष कुमार

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1388 सन् 2024

चन्द्रप्रकाश एम. तिवारी व अन्य ....वादीगण

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ....प्रतिवादीगण

Additional Affidavit on behalf of the Applicant

श्रीमान् जी,

विन्रम निवेदन है कि आवेदनकर्ताओं की ओर से माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अत्यंत आदरपूर्वक यह आवेदन प्रस्तुत कर अति-महत्वपूर्ण अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे है:-

1. यह कि उपरोक्त मामले में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 02.01.2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जो निम्नवत है :-

    1. In this original application, Applicant has raised the issue of encroachment on Nagar Park near Laxmi Taal at Jhansi, Uttar Pradesh.
    2. The similar issue had come up in OA No. 165/2021, wherein the final order issuing requisite direction was passed and for non-compliance of the said order, Execution Application No. 38/2022 is pending.
    3. List along with Execution Application No. 38/2022 on 17.03.2025.

2. यह कि OA No. 165/2021 एवं EA No. 38/2022 के संबंध में आवेदक द्वारा अभिलेखीय परीक्षण करने पर जानकारी हुई कि उक्त OA No. 165/2021 लक्ष्मीताल के निकट (Near Laxmital) झांसी महायोजना- 2021 में प्रस्तावित **नगर पार्क (Proposed city park in Jhansi Master Plan- 2021) के अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों हटाने और नगर पार्क को शीघ्र विकसित कराने हेतु दायर किया गया है। जिसे** EA No. 38/2022 के पृष्ठ संख्या 13-16 पर संलग्न है।

3. यह कि नगर पार्क के उक्त मामलों के उचित निस्तारण हेतु और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए माननीय न्यायाधिकरण द्वारा OA No. 165/2021 की फाईल तलब कर OA No. 165/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 व 25.01.2022 व 14.09.20222 के क्रम में प्रेषित आख्याओं और आख्याओं की आपत्तियों का अवलोकन किया जाना अति- आवश्यक है।

4. नगर पार्क के उक्त मामलों के उचित निस्तारण हेतु और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए माननीय न्यायाधिकरण द्वारा RA No. 33 of 2022 IN EA No. 02 of 2022 IN O.A.114 of 2021 व OA No. 165/2021 व EA No. 38/2022 और उपरोक्त OA No. 1388/2024 के साक्ष्यों, तथ्यों, अभिलेखों, आदेशों, आख्याओं और आपत्तियों का अवलोकन किया जाना अति-आवश्यक है।

5. यह कि झांसी महायोजना-2021 से दिनांक 01.01.2005 प्रभावी/लागू होने के बाद से ही लगातार अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त नगर पार्क में आरक्षित भूमि को आवासीय भूमि दर्शाकर भू-खण्डों के रूप में क्रय-विक्रय किया जा रहा है। तथा उन भू-खण्डों पर अवैध बोरवेल (Illegal borewell) कराकर, उसमें जेट पंप, सबमर्सिबल पंप इत्यादि (Installing jet pumps, submersibles etc.) स्थापित कर अवैध निर्माण करने, वाहन धोने, कपड़े धोने इत्यादि धोने और विवाह घरों, आवासीय और व्यावसायिक (Marriage Houses, Residential and Commercial) के उपयोग हेतु भूजल दोहन (groundwater exploitation) किया जा रहा है।

6. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा नगर पार्क के उक्त मामलों के उचित निस्तारण हेतु और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उक्त नगर पार्क में आरक्षित भूमि के विक्रय किये गये आवासीय भू-खण्डों के बैनामा तिथि, निर्माण वर्ष, बोरवेल स्थिति और बिजली कनेक्शन तिथि (Sale deed date, construction year, borewell status, electricity connection date,) की रिपोर्ट मंगवायें जाने पर अधिकारियों की संलिपत्ता की समस्त स्थिति स्पष्ट हो जावेगी।

7. यह कि OA No. 165/2021 एवं EA No. 38/2022 में पारित आदेशों और माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित विभिन्न वादों में माननीय न्यायालयों द्वारा सरकारी अभिलेखों और महायोजनाओं में दर्ज हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान आदि और तालाब, नदी, झील और नालों की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने एवं उनके अनाधिकृत/अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों का सर्वे कर उनको रोकने/हटाने की कार्यवाही हेतु कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किये जा रहे है एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगातार शासनादेश जारी कर संबंधित विभागों और अधिकारियों को दिशा-निर्देशों के साथ आदेशित किया जा रहा है। इसके बावजूद कर संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों और शासनादेशों क्रम में आज तक उक्त नगर पार्क के अवैध निर्माणों को हटाने व रोकने की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

8. यह कि झांसी महायोजना-2021 से दिनांक 01.01.2005 प्रभावी/लागू होने के बाद से उक्त नगर पार्क में आरक्षित भूमि के विक्रय किये गये आवासीय भू-खण्डों के बैनामों की तिथि **खतौनियों** में दर्ज दाखिल खारिज (Mutation) आदेशों के विवरण में अंकित की गयी है। उक्त नगर पार्क में आरक्षित भूमि आराजी की **खतौनियों** को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा यदि मंगवाकर देखा व पढ़ा जावें तो अधिकारियों की संलिपत्ता की समस्त स्थिति स्पष्ट हो जावेगी।

9. यह कि O.A No. 165/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के अनुपालन में प्रेषित अंतरिम आख्या (INTERIM REPORT) दिनांकित 02.04.2022 तथा अन्तिम आख्या

दिनांकित 12-09-2022 में आयुक्त महोदय, ने उक्त नगर पार्क के सम्पूर्ण क्षेत्र में 1000 से अधिक अवैध निर्माण होना स्वीकार किया है, (In the report, the Commissioner has admitted that there are more than 1000 illegal constructions in the entire area of the said City Park.) और उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों का सर्वे किया जा रहा है का उल्लेख किया गया है।

10. उक्त O.A No. 165/2021 में Applicant द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांकित 12-07-2022 पर सुनवाई के बाद दिनांक 14.09.2022 को माननीय न्यायाधिकरण ने उक्त नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। जिसका स्पष्ट उल्लेख O.A No. 114/2021 IN E.A. No. 02/2022 IN R.A. No. 33/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 में किया गया है जो निम्नवत् है।

"This Application seeks review of order of this Tribunal dated 14.09.2022 in O.A No. 165/2021, *Girja Shankar Rai & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Ors.* In fact, the grievance in the application is confined to seeking clarification that directions to remove encroachments are not confined to buffer zone of lake but also cover the area shown as park in the master plan.

2. Para 1 of the order shows that grievance about encroachments in park as per Jhansi Master Plan 2021 is mentioned. In operative part of the directions, while directing removing encroachments, park is not specifically mentioned. Consistent with the tenor of the order, direction has to cover encroachments of the park also. We clarify accordingly.

The Review Application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to the Principle Secretary, U.D, U.P, Commissioner, Jhansi, Vice Chairman, Jhansi Development Authority and DM, Jhansi by email for compliance. If any grievance survives, it will be open to the aggrieved party to take remedies afresh in accordance with law."

11. यह कि उक्त झांसी महायोजना-2021 से दिनांक 01.01.2005 प्रभावी/लागू होने के बाद से ही लगातार अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त नगर पार्क भूमि को आवासीय भू-खण्ड के रूप में क्रय-विक्रय किया जा रहा है। तथा क्रेताओं द्वारा क्रय की गयी भूमि/भू-खण्डों पर अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण (Illegal construction) किया जा रहा है।

12. यह कि उक्त OA No. 165/2021 में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 12.07.2021 को नगर पार्क के साथ लक्ष्मीताल को शामिल करते हुए एक आदेश पारित किया था जो निम्नवत है :-

1. Grievance in this application is against inaction of the statutory authorities in protecting Laxmi Tal at Jhansi from unauthorized encroachments. It is stated that

Jhansi Development Authority has been constituted by the State of UP and the Jhansi Master Plan 2021 has been prepared. However, in violation of the said Master Plan there are illegal encroachments at Laxmi Tal where a big park is proposed to be developed for tourism. Large scale illegal plotting is being done. Jhansi Development Authority has taken action against some persons including 23 persons mentioned in the application. But the action initiated has not been completed. Large scale pollution is also taking place on account of such encroachments. The applicant has also filed a copy of order dated 29.03.2019 by the Jhansi Development Authority for removing encroachments under Section 27 of the UP Urban Development Act, 1973.

3. Since similar complaints are being repeatedly filed, we find it necessary to ascertain the compliance status from a joint Committee comprising Principal Secretary, Urban Development, UP, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi.

13. यह कि उक्त OA No. 165/2021 में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25.01.2022 को एक आदेश पारित किया था जो निम्नवत है :-

1. This application has been filed by Girja Shankar Rai and others complaining inaction of statutory authorities in protection of Laxmi Tal and nearby area declared as 'green belt/green park' in Master Plan 2021 of Jhansi where there are several unauthorized encroachments and water body is also being polluted due to discharge of untreated effluent.

23. In the above backdrop of the facts, we find it appropriate to have an affirmation of factual report from a Committee comprising of different authorities and, therefore, we constitute a joint Committee comprising of MoEF&CC, CPCB, Department of Agriculture, UP, Department of Forest & Environment, UP and Divisional Commissioner, Jhansi, shall make spot inspection, examine relevant records and submit a factual report within two months. CPCB and Divisional Commissioner, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. First meeting of Committee shall be held within 15 days.

24. On the next day of hearing, Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP, shall also remain present in virtual mode.

14. यह कि OA No. 165/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के अनुपालन में प्रेषित अंतरिम आख्या (INTERIM REPORT) दिनांकित 02.04.2022 के पृष्ठ संख्या 20 में उल्लेख किया है कि "प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 से 2021 के मध्य संज्ञान में 115 प्रकरणों में कार्य रोकने के आदेश किये गये है तथा समस्त प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किये गये है। ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित प्रकरणों की सूची संलग्नक-9 अवलोकनीय है।" उक्त अंतरिम आख्या उत्तरदायी

प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों की सच्चाई छुपाकर मात्र खानापूर्ति के नाम पर मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी आख्या प्रेषित की गई थी। जिस पर वादीगण द्वारा तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आपत्ति दिनांकित 12.07.2022 दी गयी गई।

15. यह कि उक्त नगर पार्क में आरक्षित ग्राम पिछोर के गाटा संख्या 752, 753, 754, 755 व 817, 818, 819, 820, 821 और 826 लगायत 843 की भूमि रकवा लगभग 6 हेक्टेयर पर अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी विकसित की जा रहीं थी, जिसकी स्थानीय लोगो द्वारा की गयी शिकायत पर झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों और विकसित की जा रहीं अवैध कॉलोनी को रोकने व हटाने की प्रभावी कार्यवाह करने के बजायें, मात्र खानापूर्ति के नाम पर उक्त लोगों को कारण बताओं नोटिस संख्या 33/2015 व 34/2015 और 35/2015 दिनांक 20.07.2015 जारी कर कागजी कार्यवाही की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई। जिसके कारण सैकड़ों लोगो द्वारा उक्त गाटा नम्बरों पर अवैध निर्माण कर अवैध बोरवेल (Illegal borewell) करा लिया और बिजली कनेक्शन ले लिए है। उक्त नोटिसों का उल्लेख OA No. 165/2021 में प्रेषित अंतरिम आख्या दिनांकित 02.04.2022 में संलग्न अवैध निर्माणों की सूची के क्रम संख्या 1, 2 और 3 में किया गया है। उक्त नोटिस आपत्ति दिनांक 12.07.2022 में दिये गये है।

16. यह कि उक्त OA No. 165/2021 में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2022 को एक आदेश पारित किया था जो निम्नवत है :-

> 5. However, learned Principal Secretary, UD, UP, submits that upholding the law by removing the encroachment will in fact improve the law and order. We are of the view that the Rule of Law has to be upheld and it is absurd to say that if lawful action is taken law and order situation will deteriorate which means illegality should be tolerated and lawlessness allowed. It is responsibility of the State to protect Water bodies by way of completely stopping entry of sewage into the *Tal* which are significant for environment. The State is to act as trustee and not whimsically as thought by the Commissioner in taking an untenable plea to defeat the law. There is no question of deterioration of law and order in doing so.
>
> 6. In this view of the matter, we record the assurance of learned Principal Secretary, UD, UP that further remedial action will be taken for protection of water body by controlling the pollution and removing the encroachments, following due process of law. It appears that against 26 MLD of STPs only 8-10 MLD is treated which needs to be looked into and remedied. In absence of recharging source for the *Tal*, treated sewage compliant with BOD and Fecal Coliform level may be used for filling the *Tal* and growing fisheries into it.
>
> The Applications will stand disposed of.

उक्त आदेश EA No. 38/2022 के पृष्ठ संख्या 06-10 पर संलग्न है।

17. यह कि उक्त OA No. 165/2021 में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 का पालन न होने पर उक्त EA No. 38/2022 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.12.2022 को एक आदेश पारित किया था जो निम्नवत है :-

> 6. We also direct Vice Chairman, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi as also Principal Secretary, Urban Development, UP to submit a report as to what action has been taken in this regard and if no action has been taken then to show cause as to why appropriate action may not be taken against them for non-compliance of orders of this Tribunal.

18. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त OA No. 165/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 व 25.01.2022 व 14.09.20222 व और RA No. 33/2022 में पारित आदेश 10.10.2022 एवं उक्त EA No. 38/2022 में दिनांक 14.12.2022 व 10.10.2023 व 03.01.2024 व 01.03.2024 व 30.04.2024 व 09.08.2024 और 22.11.2024 के बावजूद आज तक उत्तरदायी प्रतिवादीगण ने मामले में उल्लेख नगर पार्क एवं माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रकरण में शामिल लक्ष्मीताल के अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को न तो हटाया गया और न ही रोका गया है।

19. यह कि मामले के निस्तारण और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए उपरोक्त OA No. 1388/2024 और OA No. 165/2021 एवं EA No. 38/2022 में पारित आदेशों, प्रेषित आपत्तियों, आख्याओं और अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन किया जाना अति-आवश्यक है।

प्रार्थना

माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों/साक्ष्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेकर एवं पर्यावरण/न्याय हित में निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा करें-

1. यह कि मैं आवेदनकर्ता अनुरोध करता है कि माननीय न्यायाधिकरण मेरे इस आवेदन एवं आवेदन में अंकित जानकारी को स्वीकार कर मामले की आगे की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. यह कि उपरोक्त OA No. 1388/2024 और OA No. 165/2021 एवं EA No. 38/2022 में मांगी गई राहत और प्रार्थनाएं प्रदान करने का कष्ट करें।

3. यह कि नगर पार्क के उक्त मामलों के निस्तारण और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उपरोक्त RA No. 33 of 2022 IN EA No. 02 of 2022 IN O.A.114 of 2021 व OA No. 165/2021 व EA No. 38/2022 और उपरोक्त OA No. 1388/2024 के पारित आदेशों, प्रेषित आपत्तियों, आख्याओं और अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन कर निस्तारण करने का कष्ट करें।

4. नगर पार्क में प्रस्तावित उपरोक्त भूमि के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु और पर्यावरण एवं न्यायहित में अन्य कोई आदेश और जांच/कार्यवाही जो माननीय न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे करने की कृपा करें।

5. माननीय न्यायाधिकरण से यह भी निवेदन है कि उक्त नगर पार्क के अंतिम अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाये जाने की आख्या आने के बाद ही इस प्रकरण को निस्तारित करने की कृपा करें।

दिनांक 10.03.2025

आवेदकगण

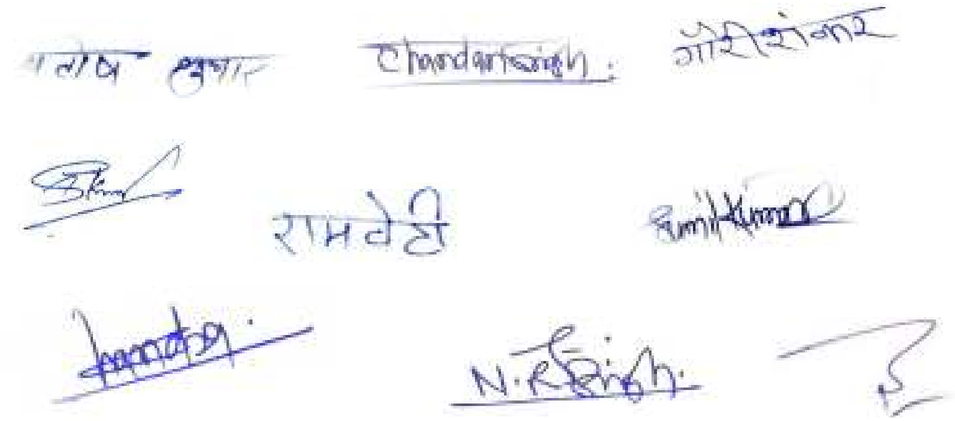

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1388 सन् 2024

चन्द्रप्रकाश एम. तिवारी व अन्य ....वादीगण

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य .....प्रतिवादीगण

शपथ-पत्र

मैं संतोष कुमार पुत्र श्री बी.लाल निवासी- नैनागढ़, थाना प्रेमनगर, झांसी, उत्तर प्रदेश। शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त मामले में वादी संख्या 7 है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है तथा यह शपथ पत्र देने के लिए सक्षम हैं।
2. यह कि प्रस्तुतीकरण (Submission) की संलग्न विषय-वस्तु सत्य एवं सही है तथा उसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूं कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 10-03-2025 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

संतोष कुमार

Serial No. 277 Date..........

Certified that the ... statement sworn before me by she/she ... Santosh Kumar whom the ... have been read ... who is identified by ... Self

Received the ...

PRAKASH NARAIN DWIVEDI
ADVOCATE
NOTARY JHANSI

10/03/25

NOTARY GOVT. OF U.P.

Item No. 02 (Court No. 01)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 165/2021

Girja Shankar Rai & Ors. Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 12.07.2021

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE M. SATHYANARAYANAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

ORDER

1. Grievance in this application is against inaction of the statutory authorities in protecting Laxmi Tal at Jhansi from unauthorized encroachments. It is stated that Jhansi Development Authority has been constituted by the State of UP and the Jhansi Master Plan 2021 has been prepared. However, in violation of the said Master Plan there are illegal encroachments at Laxmi Tal where a big park is proposed to be developed for tourism. Large scale illegal plotting is being done. Jhansi Development Authority has taken action against some persons including 23 persons mentioned in the application. But the action initiated has not been completed. Large scale pollution is also taking place on account of such encroachments. The applicant has also filed a copy of order dated 29.03.2019 by the Jhansi Development Authority for removing encroachments under Section 27 of the UP Urban Development Act, 1973.

2. This Tribunal has dealt with the matter inter-alia vide order dated 28.05.2021 *in O.A. No. 114/2021, Narendra Kushwaha v. State of UP* directing the Principal Secretary, Urban Development, UP to look into the matter and take remedial action in the light of the earlier order of this Tribunal dated 19.12.2018 in *O.A. No. 380/2018, Park Avenue Plot Holders Welfare Society v. UOI & Ors.*

3. Since similar complaints are being repeatedly filed, we find it necessary to ascertain the compliance status from a joint Committee comprising Principal Secretary, Urban Development, UP, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi.

4. By our recent order dated 5.7.2021, we have directed preparation and execution of District Environment Plans as follows:

> *"Accordingly, in view of long-time failure to comply the mandate of the Constitution adversely affecting the public health and the environment and repeated failures to comply with the earlier directions on the subject, we direct*
>
> a. *Chief Secretaries of all the States/UTs may ensure completion of District Environment Plans (DEPs) for all the Districts, in the light of orders of this Tribunal dated 26.9.2019, 19.3.2020. 29.1.2021 and the observations in the present order and upload the same on their respective websites positively by 31.10.2021.*
>
> b. *The DEPs may contain data on each environmental issue covering each city, town and village. Data may show the extent of gap in compliance of laid down norms for*
>
>   i. *Waste Management - Municipal Solid, Plastic, Bio-Medical, Electric and Electronic, Hazardous and Construction and Demolition waste*
>
>   ii. *Sewage treatment and utilisation*
>
>   iii. *Water quality – Rivers, Water bodies, Ground Water, Coastal waters and Rain water harvesting,*
>
>   iv. *Industries Pollution Control including industrial clusters*
>
>   v. *Air Quality management includes pollution due to dust*
>
>   vi. *Regulating mining/ Sand mining*

vii. *Noise pollution*

viii. *Any other issues significant in the area*

ix. *The DEP must give timelines for accomplishment of tasks backed up with budgetary support and the officers entrusted with the job, with contact details of the nodal officer at various levels in the District*

x. *Scope for public participation on remedial measures like plantations*

c. *DEPs may also contain mechanism for review at different levels.*

d. *The District Magistrates may accordingly execute the action plans by reviewing the progress on various targets at least once in a month.*

e. *All the States may accordingly consolidate the DEPs and prepare their respective State Environment Plans and upload the same on their respective websites…"*

5. The Principal Secretary, Urban Development, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. DM with local Members may have ground survey done and report to Secretary, UD for consolidated action. A status report on the subject may be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The report may specify the status of preparation and execution of DEP, number of show cause notices issued and final action taken thereupon, the status of compliance of order of this Tribunal for protection of water bodies being order dated 18.11.2020 in O.A. No. 325/2015, Lt. *Col. Sarvadaman Singh Oberoi v. UOI* such as demarcation of boundaries of Jhansi Tal, water quality, effectiveness of prevention of discharge and disposal of sewage and solid and other waste into Tal and in its catchment area, removal of encroachments, public awareness and integrated action plan for restoration within time frame.

List for further consideration on 25.10.2021.

A copy of this order be forwarded to the Principal Secretary, Urban Development, UP, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

M. Sathyanarayanan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

July 12, 2021
Original Application No. 165/2021
A

Item No. 02 (Court No. 1)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
SPECIAL BENCH

(By Video Conferencing)

Original Application No. 165/2021

Girja Shankar Rai & Ors. Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 25.01.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Narendra Kushwaha (in person)

ORDER

1. This application has been filed by Girja Shankar Rai and others complaining inaction of statutory authorities in protection of Laxmi Tal and nearby area declared as 'green belt/green park' in Master Plan 2021 of Jhansi where there are several unauthorized encroachments and water body is also being polluted due to discharge of untreated effluent.

2. Earlier, a similar complaint was received by Tribunal in OA No. 380/18; ***Park Avenue Plot Holders Welfare Society & Anr. v. Union of India & Ors.*** and OA No. 999/2019; ***Dr. Ajay Kumar v. Union of India & Ors.***, wherein illegal sale and constructions over land reserved for park and open spaces in violation of Meerut Master Plan 2021 was complained by the Applicants. State came with a stand that it is in the process of finalizing a policy for protection of parks and green belts and

stand of State was noted in the order dated 17.01.2020 in OA No. 380/2018. The relevant extract thereof is as under:

> *"The aforesaid narration of facts and the proceedings in this case wherein statements had been made on different occasions for the purpose of ensuring that* ***the land meant for park and green belt would be retained safely without encroachment had all been without any result. We find that ever-since the year 2014 when a representation was given to the concerning department and even during the pendency of the present case before us where many years have been passed, no concrete steps have been taken by State of Uttar Pradesh. We are sure that during this intervening period of more than five years much change must has taken place at the site and the land must have been used for different purposes by the individuals by claiming title in the property in question as having been purchased through registered sale deed. All this has happened due to the snail speed with which the respondent Government and its authorities have been proceeding. In view of the above, we direct the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh to take a final decision, for framing a policy or amending the relevant legislation for the purpose of saving/protecting the land which is meant for park and green belt under the Urban Master Plan of the State, on or before 31st January, 2020."***

3. Later on, State Government issued an order on 19.02.2020, directing prevention of illegal constructions against permitted land user in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. To prevent illegal sales, directions were issued to provide following details in the Sale Deed:-

> *"(A) Gata number and name of Village, Tehsil and District should be mentioned.*
>
> *(B) In case the land exists within Regulated Area/Development Area, the name of the respective Regulated Area/Development Area should be mentioned.*
>
> *(C) In case the land is proposed to be used for park, open space, greenbelt, playground and road in the Master Plan, then the landuse must be mentioned.*
>
> *(D) In the event of construction against the land-use as mentioned in the aforesaid sub-para C, the purchaser will be responsible for all legal proceedings including demolition, such consent must be mentioned in the Sale Deed."*

4. Noticing the above stand taken by State Government and other authorities, OAs 380/2018 and 999/2019 were finally disposed of vide order dated 19.01.2021. Directions issued in paras 7 and 8 read as under:

> *"7. In view of the above, the Meerut Development Authority may take further action in accordance with law which may be reviewed periodically by the Principal Secretary, Urban Development Department, UP. It may be ensured that the land use is not changed without following due process of law, which may be regulated in terms of the Master Plans by the concerned authorities. The Principal Secretary, Housing and Urban Development, UP may also ensure that the concerned Development Authorities in the State follow the Master Plan and file periodical reports to that effect.*
>
> *8. An action taken report as on 30.06.2021 may be furnished by the Principal Secretary, Housing and Urban Development, UP to the Oversight Committee headed by the Justice S.V.S. Rathore, former Judge of Allahabad High Court, who may convey its suggestions for the authorities and if necessary, send a report to this Tribunal."*

5. In respect of Jhansi Master Plan 2021, similar complaint of encroachment and inaction with regard to protection of areas identified as parks, green land, open areas etc., was raised in OA No. 114/2021; ***Narendra Kushwaha v. State of Uttar Pradesh,*** filed by one Mr. Narendra Kushwaha. Noticing the complaint, Tribunal disposed of the matter vide order dated 28.05.2021 which reads as under:

> *"Grievance in this application is against inaction in removing the encroachment and taking required action protecting the areas identified as parks, green land, open areas in the Master Plan, in violation of orders of this Tribunal dated 19.12.2018 in OA No.380/2018, Park Avenue Plot Holders Welfare Society v. UOI, and subsequent orders, and directions issued by the State of UP, Department of Housing and Urban Development. Grievance is in respect of Jhansi Development Authority and Jhansi District Administration. Particular reference is made to Mauja Pichora, with a list of about 100 encroachers. It is further stated that the details are required to be prepared and provided to the Stamp and Registration Department, as directed in several orders of the State Govt., in compliance of orders of this Tribunal.*
>
> *Though none appears for the applicant, we have perused the papers. We are of the view that the matter needs to be looked into, in the first instance, by the Principal Secretary, Urban Development, UP and*

remedial action be taken in accordance with law. Ordered accordingly.

The application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to the applicant and the Principal Secretary, Urban Development, UP by e-mail for compliance."

6. Present application has been filed raising complaint before us that not only no action has been taken in respect to the land reserved as 'green belt/park' in Jhansi Master Plan 2021 but also a water body, i.e., Laxmi Tal at Jhansi is being encroached illegally and also being polluted but no action has been taken by the concerned statutory authorities for its preservation and protection. Tribunal constituted a joint Committee comprising Principal Secretary, Urban Development, UP, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi and directed it to submit a factual report. Relevant paragraphs 3 and 5 of the order read as under:

"*3. Since similar complaints are being repeatedly filed, we find it necessary to ascertain the compliance status from a joint Committee comprising Principal Secretary, Urban Development, UP, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi.*

4. ---------x--------x--------

5. The Principal Secretary, Urban Development, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. DM with local Members may have ground survey done and report to Secretary, UD for consolidated action. A status report on the subject may be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The report may specify the status of preparation and execution of DEP, number of show cause notices issued and final action taken thereupon, the status of compliance of order of this Tribunal for protection of water bodies being order dated 18.11.2020 in O.A. No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi v. UOI such as demarcation of boundaries of Jhansi Tal, water quality, effectiveness of prevention of discharge and disposal of sewage and solid and other waste into Tal and in its catchment area, removal of encroachments, public awareness and integrated action plan for restoration within time frame."

7. Pursuant to above order, District Magistrate, Jhansi has submitted report dated 22.10.2021 stating that for compliance of Tribunal's order, he (District Magistrate) constituted a Committee comprising of (1) Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Jhansi; (2) Vice President, Jhansi Development Authority, Jhansi; (3) Additional District Magistrate, Finance and Revenue, Jhansi; (4) Additional District Magistrate (Judicial) Jhansi and, (5) Regional Officer, PCB, Jhansi or his nominee. The said Committee visited the site and found that as per Revenue records, area of Laxmi Tal is 33.068 ha (82.22 acres) comprising 60 plots. The land on the site was measured. It was found that only in Gata No. 1246, one Mr. Mangaldas Rayakwar has raised illegal construction and rest land was available without any encroachment. The illegal construction of Mr. Mangaldas Rayakwar on Gata No. 1246 has been demolished by Enforcement Squad of Nagar Nigam Jhansi. There are two more houses constructed on said plot by Mr. Maniram S/o. Mr. Babulal Rayakwar and Mr. Jitendra Rayakwar S/o. Mr. Babulal Rayakwar. The house of Mr. Maniram is in 200 sq.ft. and old while Mr. Jitendra Rayakwar constructed house under Pradhan Mantri Awas Yojna during April-May, 2021, during Covid-19 lockdown period. Both encroachers were issued notices for removal of unauthorized constructions whereupon they approached Allahabad High Court by filing writ petitions and matter is pending. **However, it is not stated that any interim order has been passed by High Court**. Nagar Nigam is monitoring the matter actively and would take appropriate action very soon. Besides this, two public temples have been constructed on the land of Laxmi Tal but their removal will not be practicable in view of law and order situation. **(This statement ignores Allahabad High Court order directing to remove encroachments from public land).** No other unauthorized construction

was found in the land of Laxmi Tal. Further, under Smart City Scheme, for preservation and protection of Laxmi Tal land and water and for its purification, steps are being taken.

8. With regard to the land in vicinity of Laxmi Tal, reserved for park, report says that an area of 170.48 ha, situated in Mauza and Dadiyapura has been reserved as public park in Master Plan 2021 of Jhansi. This entire land belong to private owners and development authority has not acquired due to financial constraints. The residential infrastructures like roads, electrification, contact roads, sanitation etc. have been arranged. In the land reserved for city parks, 67 unauthorized constructions were reported, made between 2017-2020 and for removal thereof, notices have been served and demolition orders have been passed by the competent authority. Out of 67, 34 are pending in appeal before Appellate Authority/Commissioner, Jhansi and after disposal of those appeals, appropriate action will be taken. It is also said that mostly constructions have been raised on small plots/lands by economically weaker sections and middle-class families and the constructions have been made clandestinely. 23 unauthorized constructions mentioned in Original Application, have been raised on land reserved for City Park. Appropriate action is in process. Further a board has been installed at City Park land mentioning, "the land reserved for park should not be subject of sale/purchase". The authorities have also undertaken survey of the land and would take appropriate steps for its preservation.

9. With regard to pollution of water in Laxmi Tal, report says that action has been taken by Jal Nigam and Jal Sansthan, Jhansi. As per report submitted by the said bodies, drains/sewers discharging sewage in Laxmi Tal are proposed to be bye-passed and after treatment of sewage,

treated water shall be discharged in Laxmi Tal. Work on the scheme is in process. A 26 MLD STP and three Sewage Pumping Stations have been constructed under National Lake Conservation Plan for protection of water of Laxmi Tal from being polluted. The aforesaid STP takes care of sewage generated in certain areas. Further, a Tertiary Treatment Plant (TTP) of 4 MLD is proposed and treated water of STP after its treatment from TTP shall be discharged in Laxmi Tal, **whereafter no polluted effluent will enter Laxmi Tal.**

10. With regard to sewage/solid waste and other wastes, report says that door-to-door collection has started and further action for protection of Laxmi Tal under Smart City Scheme has been taken. Some other steps are also proposed to be taken. Extract of Report submitted by District Magistrate, as received from Committee constituted by it, is reproduced as under:

"

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठकें आहूत की गई। समिति द्वारा लक्ष्मीताल की भूमि को संरक्षित करने व मूलस्वरूप में पुनः स्थापित करने हेतु की गई कार्यवाही के अनुसार वांछित बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत् है:–

झाँसी लक्ष्मी तालाब की सीमाओं का निर्धारण/चिन्हांकन एवं अनाधिकृत कब्जों को हटाया जाना

राजस्व अभिलेखों के अनुसार लक्ष्मी तालाब का कुल क्षेत्रफल कुल 60 किता रकवा 33.068 हे0/ 82.22 एकड़ है। इस भूमि की मौके पर पैमाईश करायी गई जिसमें से गाटा सं0 1246 को छोड़कर अन्य किसी भी गाटा नं0 में अवैध कब्जा नही पाया गया। भूमि मौके पर रिक्त है। गाटा सं0 1246 में एक मकान श्री मंगलदास रायकवार द्वारा निर्मित किया जा रहा था, जिसे नगर निगम के प्रर्वतन दल द्वारा मौके पर ध्वस्त कर दिया गया है। अन्य 02 मकान श्री मनीराम पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार व श्री जितेन्द्र रायकवार पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार निवासी ढिमरयाना डडियापुरा झाँसी के द्वारा मौके पर बने हुए पाये गये हैं। श्री मनीराम का मकान लगभग 200 वर्गफुट में बना है जो काफी पुराना है एवं श्री जितेन्द्र रायकवार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, मई 2021 में कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान बनाया गया है इन दोनो अतिक्रमणकर्ताओ को अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये हैं। इन नोटिसों को आधार मानकर श्री मनीराम व जितेन्द्र उपरोक्त द्वारा मा0 उच्चन्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिकायें योजित की गई हैं जो विचाराधीन है। दोनों याचिकाओं में नगर निगम की ओर से प्रभावी पैरवी एवं प्रतिवाद किया जा रहा है। शीघ्र ही इन अवैध निर्माणो के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा लक्ष्मी तालाब की भूमि में दो सार्वजनिक पुराने मन्दिर बने हुये है। जिनको हटाया जाना कानून व्यवस्था की दृष्टि से व्यवहारिक नही है। उपरोक्त के अलावा अन्य कोई अतिक्रमण लक्ष्मी तालाब की भूमि में नही पाया गया है।

इसी सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण (जांच समिति के सदस्य) द्वारा पृथक से आख्या उपलब्ध कराई गयी है। जिसकी प्रति संलग्न है। उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण की संलग्न आख्यानुसार राजस्व विभाग के माध्यम से लक्ष्मीताल की पैमाईश करायी गई है। स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण के कार्य लक्ष्मी तालाब की भूमि को सुरक्षित करने व इसके जल को शुद्ध करने हेतु कराये जा रहे है।

उपरोक्तानुसार लक्ष्मी ताल के सम्पूर्ण रकवे पर दो प्रकरणों को छोडकर कोई अवैध कब्जा नही पाया गया है तालाब की भूमि पर दो पुराने मन्दिर बने है जिनके वारे में उपरोक्तानुसार उल्लेख किया गया हैं।

उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी द्वारा लक्ष्मी ताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गयी आख्या के अनुसार इस नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि का रकवा 170.48 हे0 है, जो मौजा पिछोर एवं डडियापुरा में स्थित है यह रकवा महायोजना–2021 में नगर पार्क हेतु आरक्षित किया गया है। यह समस्त भूमि निजी काश्तकारो की है तथा इसको प्राधिकरण द्वारा वित्तीय अभाव के कारण अर्जित नही किया गया है। प्राधिकरण की आख्यानुसार इस आरक्षित भूमि में अधिकांश पुरानी आबादी पहले से ही स्थित है। जिसमें आवासीय अवस्थापना सुविधायें जैसे–सड़क, विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग, सफाई इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में वर्ष 2017–20 के मध्य कुल 67 अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है, जिनके सापेक्ष सभी प्रकरणों में काम रोकने के आदेश पारित करके स्थानीय पुलिस तथा प्राधिकरण के अवर अभियन्ता के माध्यम से तामील कराये गये है। इनमें 67 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है। 34 प्रकरण अपीलीय अधिकारी/मण्डलायुक्त झाँसी के न्यायालय में विचाराधीन है। इन सभी प्रकरणों में पैरवी करके शीघ्र ही निस्तारण कराकर मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश निर्माण छोटे–छोटे प्लाट/भूखण्ड के रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं मध्यम वर्ग के परिवारों से सम्बन्धित है। यह निर्माण चोरी–छिपे किये गये है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किए गए नगर पार्क हेतु महायोजना–2021 में आरक्षित भूमि पर 23 अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है, प्रकरणों की सूची संलग्न है। नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में जो भूमि मौके पर रिक्त है, इस पर निर्माण कार्य न होने हेतु इस आशय के बोर्ड लगाये गये है कि "भवन निर्माण करने हेतु इस आरक्षित भूमि को क्रय न किया जाए।" फोटोग्राफ संलग्न है। प्राधिकरण द्वारा नगर पार्क की भूमि के सम्बन्ध में अपेक्षित सर्वे कराया जा रहा है तथा पार्क हेतु आरक्षित भूमि को संरक्षित करने के उपाय किये जा रहे है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लक्ष्मीतालाब की भूमि को सुरक्षित करने उसे अपने मूल स्वरूप में स्थापित करने के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कार्यवाही करके अनुपालन से अवगत कराने के निर्देश दिये गये है तदक्रम में समिति द्वारा बिन्दुवार जांच करके कार्यवाही करायी जा रही है। संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

लक्ष्मी तालाब के जल की शुद्धता सुनिश्चित किया जाना

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लक्ष्मी तालाब के जल को स्वच्छ बनाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान झाँसी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गयी है जिसके अनुसार शहर के जो नाले लक्ष्मी तालाब में गिरते है उन नालों के पानी को बाईपास कर सीवेज का संशोधन करते हुए शोधित जल को पुनः लक्ष्मी ताल में डाला जाना प्रस्तावित है। इस योजना पर अभी कार्य चल रहा है।

लक्ष्मी तालाब में प्रदूषित पदार्थों आदि को जाने से रोकना

लक्ष्मी तालाब के जल में प्रदूषित पदार्थो को जाने से रोकने हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 26 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 03 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन निर्मित किये गये है। उक्त एस0टी0पी0 पर झाँसी नगर के अन्तर्गत लक्ष्मी ताल में गिरने वाले नाले एस0पी0एस0–1 के माध्यम से क्रमशः कुबेरू नाला, कसाई मण्डी नाला, लक्ष्मीगेट नाला, एस0पी0एस0–2 के माध्यम से जोशियाना नाला, बंगलाघाट नाला, ढिमरयाना नाला तथा ओम शान्ति नगर नाला को बाईपास कर सीवेज का शोधन किया जाता है। शोधन उपरान्त टरसरी ट्रीटमेन्ट के माध्यम से 4 एम0एल0डी0 शोधित जल को पुनः लक्ष्मीताल में डाला जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के पूर्ण होने पर लक्ष्मी तालाब में प्रदूषित पदार्थ नही जा सकेगें।

लक्ष्मी तालाब में एवं उसके कैचमेण्ट एरिया में सीवेज/सॉलिड वेस्ट तथा अन्य वेस्टेज को जाने से रोकना

इस सम्बन्ध में स्मार्टसिटी योजना के अन्तर्गत झाँसी नगर में तथा विशेष रूप से लक्ष्मी तालाब के कैचमेन्ट एरिया में कूड़े के डोर–टू–डोर कलैक्शन की व्यवस्था प्रारम्भ हो गई है। लक्ष्मी तालाब में वेस्टेज आदि को रोकने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम/जलसंस्थान, झाँसी द्वारा एवं स्मार्ट सिटी लि0 योजना के अन्तर्गत समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही है।

लक्ष्मी तालाब को संरक्षित करने हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाना

इस सम्बन्ध में सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण एवं अपर नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा लक्ष्मी तालाब को संरक्षित करने हेतु एन.सी.सी. कैडेट, सिविल डिफेन्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु जन–जागरूकता कार्यक्रम कराये गये है। मण्डल स्तर पर व जनपद स्तर पर जल संरक्षण एवं शहर झाँसी स्थित लक्ष्मी तालाब के जल को संरक्षित व सुरक्षित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर जन जागरण कार्यक्रय चलाये जा रहे है तथा भविष्य में भी बुन्देलखण्ड एवं झाँसी की जल से सम्बन्धित समस्याओ के दृष्टिगत जन जागरण कार्यक्रय चलाये जाते रहेगें साथ ही विभिन्न गोष्ठिओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले वाहनों पर लाउडस्पीकर्स के माध्यम से जन–जागरण हेतु लगातार प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है।

लक्ष्मी तालाब को मूलस्वरूप में निर्धारित समय के अन्तर्गत लाने हेतु समेकित कार्य योजना तैयार करना

लक्ष्मी तालाब का झाँसी नगर में ऐतिहासिक महत्व है साथ ही यह तालाब जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है इसको एक रमणीय स्थल एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के दृष्टिगत झाँसी स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कुल लागत रू0 39,49,22,826/– की परियोजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत मौके पर कार्य चल रहे है इस परियोजना में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये है:–

- तालाब के प्रवेश द्वार का जीर्णोद्धार।
- तालाब के बीच में महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति की स्थापना।
- तालाब की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण।
- तालाब के चारों तरफ पक्के नालों का निर्माण।
- तालाब के चारों तरफ सुसज्जित–पथ का निर्माण।
- लक्ष्मी मन्दिर की तरफ पार्क का निर्माण।
- पर्यटकों के लिए सेल्फी प्वाईंट का निर्माण।
- पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा।
- पर्यटकों के लिए खानपान एवं ई–शौचालय सुविधाओं का निर्माण।
- पर्यटकों के लिए नौका–विहार की सुविधा।

उपरोक्तानुसार लक्ष्मी तालाब के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व जल संरक्षण की दृष्टि से महत्व को दृष्टिगत रखते हुये लगातार विकास कार्य कराये जा रहे है लक्ष्मीतालाब की भूमि पर समिति की प्रारम्भिक जांच के अनुसार दो प्रकरणों को छोडकर कोई अनाधिकृत निर्माण नही है तालाब की भूमि पर दो मन्दिर बने है जो काफी पुराने है अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धित दो प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका विचाराधीन है जिसमें प्रभावी पैरवी की जा रही है। झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा लक्ष्मीतालाब के निकट स्थित नगर पार्क हेतु मास्टर प्लान में आरक्षित निजी काश्तकारों की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जिसका विस्तृत विवरण प्राधिकरण द्वारा उपलबध करायी गयी आख्या में दिया गया है इस आख्या की प्रति संलग्न है। लक्ष्मीतालाब को उसके मूलस्वरूप में लाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व विभाग एवं नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज रकवा मौके पर सुरक्षित है।

मात्र दो अवैध अतिक्रमण है। यह भी अवगत कराना है कि लक्ष्मी तालाब के जल को शुद्ध बनाने हेतु जल निगम एवं जल संस्थान झाँसी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है साथ ही इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये रमणीय एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु लगभग 39.49 करोड़ की लागत से झाँसी स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा विस्तृत परियोजना तैयार की गयी है जिस पर कार्य हो रहा है।

उपरोक्तानुसार लक्ष्मी तालाब की भूमि एवं उसके समीप स्थित नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में स्थलीय आख्या (Status Report) सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को प्रेषित करने की कृपा करें।

”

11. A separate report has been submitted by Vice Chairman, Jhansi Development Authority, Jhansi to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Jhansi and relevant extract of the said report, is as under:

"

जिलाधिकारी झाँसी के आदेश दिनांक 31.07.2021 के अन्तर्गत मा0 न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन के क्रम विस्तृत आख्या एवं स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने तथा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही निर्दिष्ट किये जाने व अनुपालन हेतु उक्त कमेटी गठित की गयी है।

उक्त समिति की बैठकें नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत की गयी हैं, जिसमें समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे है। समिति द्वारा आदेश के अनुपालन में लक्ष्मीताल की भूमि के अतिक्रमण को चिन्हित करके उन्हें हटावाने की कार्यवाही हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया।

समिति द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से लक्ष्मीताल की पैमाइस की जा रही है तथा स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण के कार्य कराये जा रहे है। लक्ष्मीताल के सम्पूर्ण रकवे पर राजस्व विभाग एवं नगर निगम, झाँसी के सीमांकन अनुसार अवैध कब्जे नही है, अतएव लक्ष्मीताल की भूमि के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के स्तर से अवैध निर्माण हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित नही है। लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि का रकवा 170.48 हे0 है, जो मौजा पिछोर एवं डडियापुरा में स्थित है तथा महायोजना-2021 में नगर पार्क हेतु आरक्षित है। इस भूमि के अधिकांश रकवे पर काफी पहले के निर्माण स्थित हैं। नगर निगम, झाँसी एवं विद्युत विभाग द्वारा अधिकांश पुरानी आबादी में पहले से ही अवस्थापना सुविधाएं जैसे सड़क, विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग, सफाई इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में वर्ष 2017-20 के मध्य कुल 67 अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है, जिनके सापेक्ष सभी प्रकरणों में काम रोकने के आदेश पारित करके स्थानीय पुलिस तथा प्राधिकरण के अवर अभियन्ता के माध्यम से तामील कराये गये है। इनमें 67 प्रकरणों मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वतीकरण आदेश पारित किये गये है। 34 प्रकरण अपीलीय अधिकारी/मण्डलायुक्त झाँसी के न्यायालय में विचाराधीन है। इन सभी प्रकरणों में पैरवी करके शीघ्र ही निस्तारण कराकर मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश निर्माण छोटे-छोटे प्लाट/भूखण्ड के रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं मध्यम वर्ग परिवारों से सम्बन्धित हैं। यह निर्माण चोरी-छिपे किये गये है। आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित किए गए नगर पार्क हेतु महायोजना-2021 में आरक्षित भूमि पर 23 अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है, प्रकरणों की सूची संलग्न है। नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में जो भूमि मौके पर रिक्त है, इस पर निर्माण कार्य न होने हेतु इस आशय के बोर्ड लगाये गये है कि भवन निर्माण करने हेतु इस आरक्षित भूमि को क्रय न किया जाए। मौके पर लगाए गए बोर्ड की फोटोग्राफ्स संलग्न है।

यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-डब्ल्यू-09/8-3-19-206 विविध/2018 टी0सी0 दिनांक 16.01.2019 (प्रति संलग्न हैं) के द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बैनामों में गाटा संख्या, रकवा, मौजा एवं प्राधिकरण की महायोजना में अंकित भू-उपयोग अंकित किया जाए। झाँसी विकास प्राधिकरण से मौजावार, गाटावार महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरीत पट्टिका, क्रीड़ा स्थल से सम्बन्धित सूची पंजीयन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है तथा इन भू-उपयोगों को सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज करते हुए मानचित्रों को प्राधिकरण की बेवसाइड पर प्रदर्शित/अपलोड करते हुए जनपद स्तर पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय को भी उपलब्ध करायी गयी है।

वर्तमान में विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना-2021 प्रभावी है तथा महायोजना-2031 प्राधिकरण द्वारा तैयार करायी जा रही है। शीघ्र ही इसका प्रभावी होना प्रस्तावित है। महायोजना-2031 तैयार करते समय अन्य आरक्षित भूमि के भू-उपयोग के साथ ही नगर पार्क हेतु आरक्षित इस भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्तियां प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

अंतरिम कार्यवाही आख्या अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक -

1. 23 वादों में कृत कार्यवाही की सूची।
2. मौके पर लगाए गए बोर्ड की फोटोग्राफ्स।
3. उपनिबन्धक, झाँसी-प्रथम एवं द्वितीय को प्रेषित पत्र दिनांक 07.10.2021 की प्रति। "

12. In the report, details of 23 encroachments, complained by applicants, and action taken, is given in the form of chart as under:-

"

गिरजा शंकर राय व नरेन्द्र कुशवाहा आदि के प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.06.2021 में उल्लिखित 23 प्रकरणों में कृत कार्यवाही का विवरण

क्र0 सं0	नोटिस संख्या	बिना किये विवरण	प्राधिकरण द्वारा कृतकार्यवाही	निर्मित रिहायसी भवन की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	4
1	248/2018–19	श्रीमती रामनूर्ति पाण्डेय	अवैध निर्माण हटाए जने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	निर्माण कार्य हटाया गया।
2	654/2018–19	श्रीमती द्रोपती देवी	वाद संख्या–654 दर्ज ही नही हैं।	प्रकरण विचाराधीन नही है।
3.	21/2017–18	मानवेन्द्र सिंह यादव	पत्रावली उपलब्ध नही है।	प्रकरण में नई नोटिस जारी की गयी।
4	68/2018–19	श्री शिशुपाल सिंह यादव	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
5.	199/2018–19	श्रीमती सुनीता शर्मा	अवैध निर्माण हटाए जने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
6.	193/2020–21	श्रीमती गिरजा	वाद नं0 गलत है। सही वाद सं0 68/2018–19 है। दि0 30.07.2021 को अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है।	अपील लम्बित है।
7	249/2019–20	सतीश गुप्ता	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
8	255/2019–20	विनोद वंशकार	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
9.	60/2015–16	श्रीमती सुधा तिवारी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	
10.	61/2015–16	विक्रम सिंह	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	–
11	62/2015–16	श्रीमती मूर्ति देवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
12.	63/2015–16	श्रीमती रामदेवी सिंह	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	
13.	64/2015–16	पुष्पेन्द्र कुमार	अवैध निर्माण हटाए जाने का दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
14	36/2016–17	श्रीमती ममता देवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	
15	37/2016–17	श्रीमती जमीला बानो	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
16.	38/2016–17	बब्लू	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश। दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	
17	39/2016–17	रिती श्रोतिया	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
18.	40/2016–17	श्रीमती सुकृता देवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
19.	41/2016–17	श्रीमती संध्यादेवी	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	
20.	119/2016–17		वाद संख्या–119 दर्ज ही नही हैं।	
21	10/2017–18	पप्पू ठाकुर	अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
22.	12/2017–18	रेखापाल	हटाए का दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।
23.	20/2017–18	जितेन्द्र कुमार	हटाए का दिनांक 30.07.2021 निर्गत।	अपील लम्बित है।

"

13. The aforesaid chart shows that out of 23 matters, 13 are pending in appeal, in 01 matter, illegal construction has been removed, in 01 matter even case has not been registered and in one matter notice was issued but thereafter file is not traceable and in remaining matters, orders for demolition were passed on 30.07.2021 but thereafter nothing has been done. Thus, in 07 matters no action has been taken despite order of demolition passed on 30.07.2021. No reason has been given as to why said orders have not been executed so far.

14. A separate report has been filed by Additional Chief Secretary, Urban Development Department, UP, vide letter dated 21.01.2022 and the said report is based on the compliance report sent by District Magistrate, Jhansi. The information submitted before us is based on the report of District Magistrate, Jhansi and placed before us in the form of chart, by Additional Chief Secretary, and it reads as under:

"

	Issue	Status compliance as per DM Jhansi report
1	The Ground Survey and the Demarcation of Boundaries of Jhansi Laxmi Tal/ Identification and removal of the encroachments around it	According to the Land records avaible, the total area of Laxmi Tal is 33.068 Hectare or 82.22 Acres. While conducting the local survey on ground, no illegal construction or encroachment incidence were found to be going on except on Gata Number 1246, on which construction activity was being done illegally. This was not only stopped but also demolished by the concerned Municipal authorities. It is to be mentioned that the final demarcation of the area recorded under the Laxmi Tal is being done by the method of Total Station Survey, which is under progress. The Report dated 15-12-2021 submitted by VC, JDA states that a total of 170.48 Hectare of land area is reserved for the city park under the Master Plan 2021, near Laxmi Tal, which is situated in Mauja Pichore and Dadiapura. Out of

		170.48 Hectare Land, 44.78 Hectare land is government land on which the city park called Narayan Bagh is already developed and is encroachment free. The balance portion of 125.74 Hectare land is under the legal ownership of private individuals .As per survey report 101.40 Hectare land has the old Abadi/settlements, whereas approxing only 24.34 hectare land is still vacant. After the notification made for the master plan 2021 during the year 2017 to 2020, total 67 illegal constructions are reported and legal action by the Development Authority of Jhansi is being undertaken. To secure the land reserved for the city park, the government has issued various orders through Housing and Urban Planning Department, Section-3 on date 19.12.2018, 16.01.2019 and 19.02.2020 in the matter of OA. No. 380/2018 Park Avenue plot holders welfare society Vs Union of India & Ors, Order dated - 19.12.2018 and the compliance is being ensured as under: A- Notice boards have been put up on site with the message to public not to buy land or do any construction activities on the said land which would be in contravention of master plan and land use. B- It has been requested to Stamp and Registry Department to mention land use of master plan in respective land and revenue records. C- The list of parks, Open area, Green Belt and Play grounds etc.

		proposed under the Master Plan-2021 of the Jhansi Development Authority has been made available to the Stamp and Registry Department to mention land use of respective "Gata Numbers" in the Land & Revenue maps and upload the updated map on concerned website. D- The officials of Jhansi Development Authority are regularly visiting the concerned area to avoid any further illegal construction or other similar activities.
2	**Water Quality of Laxmi Tal/ Prevention of Pollutantsfrom entering into Laxmi Tal and it's Catchment Area.**	It is submitted that to improve water quality of Laxmi Tal, coordinated efforts have been undertaken by U.P. Jal Nigam and Jal Sansthan of Jhansi. Under the National Lake Conservation Program, a STP of capacity 26 MLD and 03 Numbers of Sewage Pumping Stations have been established recently, which help in treatment of sewarage. As per reports, there is no untreated water being discharged into Laxmi Tal presently. Special arrangements have been done to ensure 100% door to door garbage collection in the catchment area of Laxmi Tal.
3	**Public Awareness for Conservation of Laxmi Tal**	For conservation of Laxmi Tal, Jhansi Development Authority and Municipal Corporation of Jhansi have jointly conducted several public awareness programmes. Institution like NCC have

		also been roped in for this initiative. All the motorized vehicles engaged in door-to-door collection and transportation of Garbage have been equipped with public address system/loudspeakers and are being used for the IEC Campaign with the message of segregation of waste at source and appeal to the public to cooperate with the authorities in the development and beautification of Laxmi Tal.
4	**Restoration of Laxmi Tal**	It is to submited that the Laxmi Tal has its historical importance. Under Smart City Mission, Jhansi a project of Rupees 39.49 Crore has been prepared to further develop Laxmi Tal as a tourist spot with several development for restoring the scenic beauty of the Tal. Some of the features of project are as follows: A- Beautification of the entrance gate of Laxmi Tal. B- Installation of the statue of Queen Laxmi Bai at Laxmi Tal. C- Cleaning and beautification of Laxmi Tal. D- Construction of Concrete drains around Laxmi Tal. E- Construction of well decorated

		walkways around Laxmi Tal. F- Construction of a new park in the side of Laxmi Temple . G- Selfie Point for the Tourists. H- Development of parking facilities for the Tourists. I- Establishment of food courts and Smart toilets. J- Development of boating facilities and jetty.
5	**The preparation of the District Environmental Plan**	The District Environmental Plan has been prepared.

"

15. We find that item 2 of the chart with regard to water quality of Laxmi Tal, Additional Chief Secretary has said that as per report, no untreated water is being discharged into Laxmi Tal, presently. But report of District Magistrate, which we have quoted above, shows differently and says that many steps are in the stage of planning and only after execution thereof, there would be complete stoppage of discharge of polluted effluent in Laxmi Tal water but presently, 26 MLD STP is not able to do complete job. It is really unfortunate that a Senior Officer like Additional Chief Secretary has not carefully read the report and made a wrong statement in its own report.

16. Further we find that none of the said reports can be said to comply Tribunal's order in entirety. No report refers to District Environment Plan for which there was a specific direction. Reports also withhold information like quantity of sewage entering Laxmi Tal, water quality

data, time for completion of TTP, action plan, if any, for desiltation and cleaning of water etc.

17. Maintenance of water body is prime responsibility of statutory authorities as well as statutory regulators under Environmental Laws and other enactments dealing with public health and similar issues. Similarly, a land reserved for green belt/park in the Master Plan whether belongs to State or private owners cannot be allowed to be used for raising any construction. With respect to the area reserved for 'green belt/park', it has been repeatedly held by Supreme Court that such spaces cannot be changed to residential or commercial one.

18. In ***Lal Bahadur v. State of UP & Others, (2018)15SCC407***, change of master plan and converting green area into residential one was considered. The issue was, whether such conversion is conducive to protection of environment or not. In the master plan of 1995 of Lucknow, area in dispute was reserved as green belt. In master plan 2021, the same area, shown earlier as green belt, was converted as residential. This part of master plan 2021 was challenged before Lucknow bench of Allahabad High Court. Writ petition was dismissed. The matter came in appeal before Supreme Court. Court held in para 12 of judgment that change of area from green belt to residential is in violation of Article 21, 48A and 51A(g) of the Constitution. Reliance was placed on ***Bangalore Medical Trust v B.S. Muddappa & Others, (1991)4SCC54***, wherein Court had said that protection of environment, open spaces for recreation and fresh air, playground for children, promenade for the residents and other conveniences or amenities are matters of great public concern and a vital interest to be taken care of in a development scheme. Public interest in the reservation and preservation of open spaces for parks and

playgrounds cannot be sacrificed by leasing or selling such sites to private persons for conversion to some other use. Court also relied on an American Supreme Court Judgment ***Agins vs. City of Tiburon, [447 us 255 (1980)],*** wherein Court said: *'... it is in the public interest to avoid unnecessary conversion of open space land to strictly urban uses, thereby protecting against the resultant adverse impacts, such as ...... pollution, ... destruction of scenic beauty, disturbance of the ecology and the environment, hazards related geology, fire and flood, and other demonstrated consequences of urban sprawl'.*

19. In para 15, Court said that, "*This Court had clearly laid down that* ***such spaces could not be changed from green belt to residential or commercial one.*** *It is not permissible to the State Government to change the parks and playgrounds contrary to legislative intent having constitutional mandate, as that would be an abuse of statutory powers vested in the authorities.* Court also observed, when master plan was prepared earlier and authorities found importance of such space, it was their bounden duty not to change its very purpose when they knew very well the importance of this place to be kept as open space. Court said,

> ***"****The* ***importance of park is of universal recognition****. It was against public interest, protection of the environment and such spaces reduce the ill effects of urbanisation, it was* ***not permissible to change this area into urban area as the garden/ Greenbelt is essential for fresh air, thereby protecting against the resultant impacts of urbanization, such as pollution etc****. The provision of the Act of 1973 and other enactments relating to environment could not be permitted to become statutory mockery by changing the purpose in the master plan from green belts to residential one. Authorities are enjoined with duty maintain them as such as per doctrine of public trust.****"***

20. Ultimately, Court quashed Master Plan 2021 changing use of area in question from greenbelt to residential and said that it shall be held in trusteeship only for the purpose of park in future.

21. Despite the law of land referred above and the orders passed by Tribunal expressing similar views, we find that approach of concerned authorities is very casual, lackadaisical and non-serious. We do not find any element of commitment, sincerity, honest intention and will on the part of authorities in taking effective steps for preservation and protection of green belt/land reserved for park in Master Plan.

22. Applicants have also filed objections to the report of District Magistrate and almost on every statement of fact, given by District Magistrate, applicants have submitted that report is misleading, incorrect and contrary to actual position existing on the site. Applicants have also placed on record a list of almost 100 sale deeds of parts of the land reserved as 'green belt/park' showing that sale deeds have been executed in 2020-21 itself without giving details of the property as mentioned in Government order and no effective action has been taken by authorities concerned. The objections of applicants against District Magistrate's report are reproduced as under:

"

1. यह कि जिलाधिकारी महोदय, ने जानबूझकर मा. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–07–2021 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करने के बजाये, लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं व अवैध निर्माणकर्ताओं/अतिक्रमणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने एवं अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों को बचाने के लिए, मात्र खानापूर्ति के नाम पर स्थलीय निरीक्षण किए बिना मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी उक्त स्थलीय आख्या (Status Report) दिनांकित 22–11–2021 को तैयार कराकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की है जो खारिज होने योग्य है।

2. **जिलाधिकारी महोदय, के कथनानुसार**– लक्ष्मीतालाब की भूमि को मूल स्वरूप में लाने उसके जल को संरक्षित करने प्रदूषित पदार्थों को तालाब में न जाने देने तालाब की भूमि के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व पर्यावरण सम्बन्धित महत्व के दृष्टिगत विकसित करने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त नगर निगम झाँसी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। गठित समिति द्वारा बैठके करके तथा स्थलीय निरीक्षण करके लक्ष्मी तालाब की भूमि एवं इसके निकट नगर पार्क हेतु मास्टर प्लान 2021 में आरक्षित निजी काश्तकारों की भूमि के सम्बन्ध में स्थलीय आख्या (Status Report) तैयार की गई है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झांसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क और भूजल संरक्षण, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिगत प्राचीन काल में विकसित ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वालों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय, द्वारा गठित की गई समिति ने न तो लक्ष्मी तालाब की सीमाओं की पैमाईश कर सीमाओं का निर्धारण/चिन्हांकन किया और न ही नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों का सर्वे कर इनको हटाने की कार्यवाही की है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वालों से मिलीभगत होने का कारण जिलाधिकारी महोदय, ने नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों को बचाने के लिए, समिति द्वारा मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी स्थलीय आख्या (Status Report) तैयार कराकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की है जो खारिज होने योग्य है।

3. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार– लक्ष्मी तालाब में प्रदूषित पदार्थों आदि को जाने से रोकना–** लक्ष्मी तालाब के जल में प्रदूषित पदार्थों को जाने से रोकने हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 26 एम.एल. डी. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 03 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन निर्मित किये गये है। उक्त एस०टी०पी० पर झाँसी नगर के अन्तर्गत लक्ष्मी ताल में गिरने वाले नाले एस०पी०एस०–1 के माध्यम से क्रमशः कुबेरू नाला, कसाई मण्डी नाला, लक्ष्मीगेट नाला एस०पी०एस०–2 के माध्यम से जोशियाना नाला, बंगलाघाट नाला, ढिमरयाना नाला तथा ओम शान्ति नगर नाला को बाईपास कर सीवेज का शोधन किया जाता है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– शहर के नालों का जहरीला एवं दुर्गंध देने वाला गंदा पानी लक्ष्मी तालाब के साथ साथ राजकीय उद्यान नारायाण बाग में भी जा रहा है, जिससे नारायाण बाग में उपरोक्त नालों का गंदा पानी कीचड़ दलदल के रूप में जमा हो गया है जिसके कारण वहां स्थित हरे भरे वृक्ष सूखते जा रहे है, इस जहरीले पानी को पीने से नारायाण बाग के कई पशु व पक्षी मर हो चुके है। और नारायाण बाग में शुद्ध वातावरण की आशा से आने वाले लोगों को इस दलदल/कीचड़ की दुर्गंध से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। **अवलोकन हेतु मौके के फोटोग्राफ पेश है।**

4. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार–** लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि का रकवा 170.48 हे0 है, जो मौजा पिछोर एवं डडियापुरा में स्थित है तथा महायोजना–2021 में नगर पार्क हेतु आरक्षित है। इस भूमि के अधिकांश रकवे पर काफी पहले के निर्माण स्थित हैं। नगर निगम, झाँसी एवं विद्युत विभाग द्वारा अधिकांश पुरानी आबादी में पहले से ही अवस्थापना सुविधाएं जैसे सड़क, विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग, सफाई इत्यादि की व्यवस्था की गयी है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– " झांसी महायोजना 2021 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायण बाग एवं समीप की आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था। नारायण बाग का स्थल सुरक्षित है एवं विकास कार्य प्रगति पर है लेकिन इसके समीप आरक्षित नगर पार्क की भूमि पर 12.4 हेक्टेयर में प्रतिकूल आवासीय विकास हो चुका है। वहां दिन प्रतिदिन अनधिकृत निर्माण का कार्य प्रगति पर है फिर भी वर्तमान में बहुत बड़ा क्षेत्र नगर पार्क हेतु उपलब्ध है जिसको सुरक्षित करना पर्यावरण एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।" **इससे सपष्ट होता है कि नगर पार्क के गाटा संख्या की सूची अधूरी बनाई गई है और नगर पार्क का 27.9** हेक्टेयर **रकवा कम बताया गया है। (पृष्ठ संख्या 7 की छायाप्रति पेश की जा रही है।)**

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से डाउनलोड की गई बैनामों की सूची में 2017 से 2021 के दौरान उक्त नगर पार्क की भूमि को आवासीय बताकर विक्रय की गई भूमि के लगभग **600** से अधिक बैनामे पंजीकृत किए गये है जिस पर वर्तमान में **पुलिस प्रशासन व झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण कर अवैध कॉलोनिया विकसित की जा रही है** और इन अवैध निर्माणों/अवैध कॉलोनियों में झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के उच्चाधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों को लिखित एवं मौखिक स्वीकृति देकर सड़क, बिजली, पानी आदि के कई प्रकार के विकास कार्य अवैध रूप से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर सरकारी खर्चे पर कराये जा रहे है। इससे स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी महोदय, ने समिति से नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों का सर्वे कराये बिना मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी स्थलीय आख्या (Status Report) तैयार कराकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की है जो खारिज होने योग्य है। **(डाउनलोड की गई बैनामों की सूची की छायाप्रति पेश की जा रही है।)**

5. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार–** यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या–डब्ल्यू–09/8–3–19–206 विविध/2018 टी०सी० दिनांक 16.01.2019 (प्रति संलग्न है) के द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बैनामों में गाटा संख्या, रकवा, मौजा एवं प्राधिकरण की महायोजना में अंकित भू–उपयोग अंकित किया जाए। झाँसी विकास प्राधिकरण से मौजावार, गाटावार महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरीत पट्टिका, कीड़ा स्थल से सम्बन्धित सूची पंजीयन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है तथा इन भू–उपयोगों को सजरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज करते हुए मानचित्रों को प्राधिकरण की बेवसाइड पर प्रदर्शित/अपलोड करते हुए जनपद स्तर पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय को भी उपलब्ध करायी गयी है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– उक्त शासनादेश जारी होने के दो वर्ष आठ माह का समय व्यतीत जाने व मामला मा. न्यायाधिकरण में पहुंचने के बाद जेडीए उपाध्यक्ष महोदय, ने शासनादेश में दिए गए दिशा–निर्देशों कि मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए अवैध निर्माणों का सर्वे कराये बिना, अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने/रोकने के बजाये, केवल दिनांक 07.10.2021 को महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरीत पट्टिका, कीड़ा स्थल से सम्बन्धित अधूरी सूची उप निबंधक कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

6. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार–** नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में वर्ष 2017–20 के मध्य कुल 67 अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है, जिनके सापेक्ष सभी प्रकरणों में काम रोकने के आदेश पारित करके स्थानीय पुलिस तथा प्राधिकरण के अवर अभियन्ता के माध्यम से तामील कराये गये है। इनमें 67 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है। 34 प्रकरण अपीलीय अधिकारी/मण्डलायुक्त झाँसी के न्यायालय में विचाराधीन है। इन सभी प्रकरणों में पैरवी करके शीघ्र ही निस्तारण कराकर मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की मिलीभगत से नगर पार्क के भू–उपयोग वाली भूमि को आवासीय बताकर भू–खण्ड विक्रय किए जा रहे एवं उन भू–खण्डों पर अवैध निर्माण कर बिजली, पानी के कनेक्शन भी झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से संबंधित विभागों के द्वारा दिए जा रहे है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज संदर्भ संख्या 40016621010879 दिनांक 03.07.2021 में जेडीए सचिव द्वारा लगाई गई आख्या में उल्लेख किया गया कि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि पर 500 से अधिक भवन निर्मित है तथा वहां मूल–भूत सुविधाएं यथा नाली, सड़क, बिजली आदि के कई प्रकार के विकास कार्य विभिन्न विभागों द्वारा कराया जा चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी महोदय, ने समिति से नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों का सर्वे कराये बिना मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी स्थलीय आख्या (Status Report) तैयार कराकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की जो खारिज होने योग्य है। **(आख्या की छायाप्रति पेश की जा रही है।)**

7. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार–** यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश निर्माण छोटे–छोटे प्लाट/भूखण्ड के रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं मध्यम वर्ग परिवारों से सम्बन्धित हैं।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों मिलीभगत से सैकड़ों सरकारी

कर्मचारियों, व्यवसायियों, बैनमी संपत्तिधारी राजनेताओं ने आवासीय/व्यवसायी निर्माण कर लिए हैं और वर्तमान में भी सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण किये जा रहे हैं।

8. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार–** यह निर्माण चोरी–छिपे किये गये है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि नगर पार्क की भूमि पर झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों-अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं से सुविधा शुल्क लेकर खुल्लम खुल्ला अवैध निर्माण करवाएं है और करवाएं जा रहें है। इन अवैध निर्माणों की शिकायतें एवं सूचनाएं लगातार झांसी प्रशासन और जेडीए के उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर व जनसुनवाई पोर्टल व ई मेल प्रेषित कर एवं मोबाईल पर दी जाती रही है। परन्तु भूखंड बेचने और अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों से **पुलिस प्रशासन व झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण न तो अवैध निर्माणों को रोका गया और न ही आज तक एक भी अवैध निर्माण को हटाया गया है। (अवलोकन हेतु अवैध निर्माणों के फोटोग्राफ पेश किए जा रहे है।)**

श्रीमान जी को यह भी अवगत कराना है कि उक्त नगर नगर पार्क की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माणों की शिकायतों पर दिनांक 28 मार्च 2019 व 17 जून 2020 और 26 जुलाई 2020 को जेडीए उपाध्यक्ष, श्रीमान सर्वेश कुमार दीक्षित जी ने स्वयं स्थल पर पहुंच कर मौके पर किए जा रहे कई अवैध निर्माणों को देखा और प्लाट विक्रेताओं/निर्माणकर्ताओं से कार्यालय में आकर मिलने को कहा था। जेडीए उपाध्यक्ष और सचिव ने कार्यालय में मिलने आये उन प्लाट विक्रेताओं/निर्माणकर्ताओं से प्रति निर्माण का मन–माफिक सुविधा शुल्क लेकर पूर्व में जेडीए की ओर से की जा रही सभी कार्यवाहियों को बंद कर दिया और प्रति निर्माण का सुविधा शुल्क देकर निर्माण शुरू करने की अनुमति दे दी जिसके बाद सभी निर्माणकर्ताओं ने उक्त अर्धनिर्मित निर्माणों को पूर्ण कर उन अवैध निर्माणों में बिजली, पानी के कनेक्शन लेकर निवास करने लगे है। जिसकी पुष्टि पूर्व में जारी किए गए नोटिस संख्या 33, 34, 35, 60, 61, 62, 63, 64, सन् 2015–16 व 36, 37, 38, 39, 40, 41, 119 सन् 2016–17 व 10, 12, 20, 21 सन् 2017–18 व 68, 199, 248, 654 सन् 2018–19 व 249, 255 सन् 2019–20 व 193 सन् 2020–21 में उल्लेख निर्माणों की स्थलीय जांच कराकर की जा सकती है। उक्त नगर पार्क में आरक्षित आराजी संख्या 753 से 755 तक 818 से 821 तक 826 से 840 आदि मौजा पिछोर की भूमि को आवासीय के रूप में विभाजित कर भूखंड बेचे जा रहे थे और उन भूखंडों पर अवैध निर्माण किए जा रहे थे जिसकी कई शिकायतें करने के बाद दिनांक 20.07.2015 को झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से इन अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही करने के बजाये मात्र खानापूर्ति के नाम पर कुछ भूखंड बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत नोटिस सं. 33/2015–16, 34/2015–16 और 35/2015–16 जारी कर औपचारिकता कर ली गई है। जिसके बाद सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों, व्यवसायियों, बैनामी संपत्तिधारियों और राजनेताओं ने अवैध आवासीय/व्यवसायी निर्माण कर लिए हैं और वर्तमान में भी सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण किये जा रहे हैं। जिसकी लगातार शिकायतें की जाती रहीं है, परन्तु भूखंड बेचने और अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों से झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण न तो अवैध निर्माणों को रोका गया और न ही आज तक एक भी अवैध निर्माण को हटाया गया है। **नोटिस सं. 33/2015–16, 34/2015–16 और 35/2015–16 की छायाप्रति पेश की जा रही है।**

9. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार–** नगर पार्क हेतु आरक्षित भूमि में जो भूमि मौके पर रिक्त है, इस पर निर्माण कार्य न होने हेतु इस आशय के बोर्ड लगाये गये है कि भवन निर्माण करने हेतु इस आरक्षित भूमि को क्रय न किया जाए।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– जेडीए उपाध्यक्ष महोदय, ने कागजी कार्यवाही की औपचारिकता पूरी करने के उद्देश्य से मात्र खानापूर्ति के नाम पर बोर्ड लगाये गये थे जो बाद में भूखंड बेचने और अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के द्वारा हटवा दिए गये।

10. **यह कि समिति की तथाकथित स्थलीय आख्या (Status Report) के अनुसार–** वर्तमान में विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना– 2021 प्रभावी है तथा महायोजना–2031 प्राधिकरण द्वारा तैयार करायी जा रही है। शीघ्र ही इसका प्रभावी होना प्रस्तावित है। महायोजना–2031 तैयार करते समय अन्य आरक्षित भूमि के भू–उपयोग के साथ ही नगर पार्क हेतु आरक्षित इस भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्तियां प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

जब कि उक्त कथन की वास्तविकता/सत्यता यह है कि– महायोजना में पर्यावरण एवं हरियाली और मनोरंजन से संबंधित प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं की मिलीभगत से एवं इन भू–माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से झांसी प्रशासन और विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि को आवासीय करने के उद्देश्य से महायोजना–2031 तैयार कराने की कौशिश की जा रही है। इसी कारण से मा. न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की ओर से महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों का न तो सर्वे किया गया है और न ही उन अवैध निर्माणों के विरुद्ध हटाने/रोकने की कार्यवाही की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि जिलाधिकारी महोदय, ने समिति से नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों का सर्वे कराये बिना मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी स्थलीय आख्या (Status Report) तैयार कराकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की जो खारिज होने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

11. यह कि झांसी महायोजना में लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित उक्त नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं से झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण जेडीए की ओर से आज तक एक भी अवैध निर्माण को हटाया/गिराया नहीं गया है। जिसकी जांच जनहित, पर्यावरण और न्याय हित में किया जाना अति आवश्यक है।

12. यह कि झांसी महानगर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए झांसी महायोजना में प्रस्तावित किये गये नगर पार्क, पार्क, खुले स्थल, हरीत पट्टिका, कीड़ा स्थल की भूमि पर झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की मिलीभगत किये जा रहे अवैध निर्माणों के कारण झांसी महानगर में हरियाली का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। जिससे झांसी महानगर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।

13. यह कि नगर पार्क के अवैध निर्माणों की शिकायतों और शासन द्वारा दिनांक 05 मई 2017 को निर्गत शासनादेश संख्या 167/8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी. का अनुपालन करते हुये

तत्कालीन जेडीए सचिव/नगर मजिस्ट्रेट झाँसी ने दिनांक 18 अगस्त 2017 को जेडीए के अधिकारियों व क्षेत्राधिकारी नगर और राजस्व विभाग के लेखपाल के साथ उपरोक्त नगर पार्क में प्रस्तावित भूमि के अवैध निर्माणों का स्थल निरीक्षण किया गया था। उक्त स्थल निरीक्षण के दौरान जेडीए सचिव ने जेडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि राजस्व विभाग के लेखपाल के साथ नगर पार्क में प्रस्तावित भूमि के अवैध निर्माणों का सर्वे कर उन निर्माणों को हटाने की कार्यवाही करने के आदेश दिये थे। जेडीए सचिव के उपरोक्त आदेश पर नगर नियोजक, जितेन्द्र सिंह व अवर अभियंता और लेखपाल द्वारा नगर पार्क में प्रस्तावित भूमि के अवैध निर्माणों का सर्वे किया गया था। उक्त सर्वे के उपरान्त सेकड़ों अवैध निर्माणों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किये गये, वर्तमान जेडीए उपाध्यक्ष व सचिव ने अवैध प्लाटिंग करने वाले व्यक्तियों से सांठगांठ कर उक्त सर्वे व नोटिसों की फाइलों को गायब कर कार्यवाही बंद कर दी। जिसकी जांच जनहित, पर्यावरण और न्याय हित में किया जाना अति आवश्यक है।

14. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, में दर्ज इस प्रकरण में पैरवी कर रहे याचिकाकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को पैरवी से रोकने और दबाव बनाने लिए, नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले अराजक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कई माध्यमों से परेशान किया जा रहा है।

15. यह कि नगर पार्क के अवैध निर्माणों की शिकायत करने पर अवैध निर्माण करने/कराने वाले सुदीप कुमार ने आपत्तिकर्ता (नरेन्द्र कुशवाहा) से कहा कि सदर विधायक मुझे अपना छोटा भाई मानते है, विधायक जी के कहने पर मैने नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्तियों से रुपया लेकर विधायक जी के द्वारा बताए गए विभागों के अधिकारियों को रुपया देकर अवैध कॉलोनियां में रोड़ और बिजली-पानी की लाईन डलवाई है और अवैध निर्माण करवा रहा हूं जिससे मुझे और विधायक जी का लाखों रुपया मिलता है। विधायक जी कहने पर ही जेडीए सचिव द्वारा अवैध निर्माणों की शिकायतों पर झूठी आख्या लगाकर निस्तारण किया जा रहा है। 12 अगस्त 2021 को सुदीप कुमार, रामनरेश शर्मा, अशोक कुशवाहा, विनोद वंशकार, जितेन्द्र श्रीवास्तव और अर्जुन, हरिराम कुशवाहा ने आपत्तिकर्ता (नरेन्द्र कुशवाहा) को धमकी देते हुए कहा था की जेडीए सचिव ने हम सभी लोगों से मु. 30000/- रुपये निर्माण करने के और मु. 50000/- रुपये छत डालने के लिये है। और जेडीए सचिव ने हमसे कहा है की हमारी सेटिंग्स जेडीए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष से है, जिनको में अवैध निर्माण कराने से मिलने वाले रुपयों में से हिस्सा देता हूं जो शासन तक जाता है, जेडीए सचिव ने कहा है कि तुम लोग निश्चिंत रहो तुम्हारे निर्माणों को ना तो सील किया जाएगा और नाही तोड़ा जाएगा। केवल दिखावट के लिये पूर्व की भांति कुछ नोटिस दिये जा रहे जिनको बाद में गायब कर कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। और धमकी दी थी कि तुम शिकायतें बंद कर दो वरना विधायक जी से कहकर तुमको ठिकाने लगवा देंगे। जेडीए में रुपया देकर सुदीप कुमार उर्फ महाराज ने अशोक कुशवाहा के पूर्व में कई निर्माण कराये है और जेडीए सचिव को रिश्वत/घूस देकर अशोक कुशवाहा द्वारा किए जा रहे नव निर्मित निर्माण पर 15 अगस्त 2021 को आरसीसी लेंटर डालवा दिया है। एवं जेडीए सचिव को रिश्वत/घूस देकर सुदीप कुमार उर्फ महाराज के साथ साथ कई व्यक्तियों द्वारा वर्तमान में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिनकी शिकायत करने पर जेडीए उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा न तो इन अवैध निर्माणों को रुकवाया जा रहा और न ही हटाया जा रहा है। जिसकी जांच जनहित, पर्यावरण और न्याय हित में किया जाना अति आवश्यक है।

16. यह कि पर्यावरण में फैल रहें प्रदूषण को नियंत्रण करने व धरा पर हरियाली बिखेरने के लिए वनों की भूमि और महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टियों, पार्कों, क्रीड़ा स्थलों की भूमियों को

अतिक्रमण व कब्जा मुक्त कराकर विकसित नहीं कराया गया तो निश्चित ही केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लाखों–करोड़ों रुपय खर्च करके बनाई गई महायोजनाएं एवं पौधारोपण जैसी चलाई जा रही महतपूर्ण योजनाएं विफल हो जयेगी। जिससे पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलन रखने का दृ ढ़ संकल्प व स्वप्न अधूरा रह जाएगा जिसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में केवल जीव–जंतुओं ही नहीं बल्कि मानव का जीवन भी धरा से विलुप्त होने का खतरा बढ जायेगा। ”

23. In the above backdrop of the facts, we find it appropriate to have an affirmation of factual report from a Committee comprising of different authorities and, therefore, we constitute a joint Committee comprising of MoEF&CC, CPCB, Department of Agriculture, UP, Department of Forest & Environment, UP and Divisional Commissioner, Jhansi, shall make spot inspection, examine relevant records and submit a factual report within two months. CPCB and Divisional Commissioner, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. First meeting of Committee shall be held within 15 days.

24. On the next day of hearing, Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP, shall also remain present in virtual mode.

A copy of this order be forwarded to the Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP by email.

List for further consideration on 04.04.2022.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 25, 2022
Original Application No. 165/2021
AVT

Item Nos. 03 & 04 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 165/2021

Girja Shankar Rai & Ors. Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

WITH

Execution Application No. 02/2022
IN
Original Application No. 114/2021
(I.A. No. 164/2022)

Narendra Kushwaha Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent

Date of hearing: 14.09.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Respondent(s): Mr. Amrit Abhijat, Principal Secretary, UD, Govt. of UP
Mr. Sanjay Goel, Commissioner, Jhansi
Mr. Ravindra Kumar, DM/VC JDA
Mr. Pulkit Garg, Municipal Commissioner with Mr. Rachit Mittal, Advocate
Ms. Soni Singh, Advocate for CPCB

ORDER

1. Since both the matters are inter-connected, the same are taken up together. Grievance in OA 165/2021 is against inaction of the statutory authorities in protecting *Laxmi Tal* at Jhansi from unauthorized encroachments and pollution and preventing entry of untreated sewage and sullage. Jhansi Development Authority has been constituted by the

State of UP and the Jhansi Master Plan 2021 has been prepared but in violation of the said Master Plan, there are illegal encroachments at Laxmi Tal where a big park is proposed to be developed for tourism. Large scale illegal plotting is being done. Jhansi Development Authority has taken action against some persons including 23 persons mentioned in the application. But the action initiated has not been completed. Large scale pollution is also taking place in the lake. The applicant has also filed a copy of order dated 29.03.2019 by the Jhansi Development Authority for removing encroachments under Section 27 of the UP Urban Development Act, 1973.

2. The application was considered along with O.A. No. 114/2021, *Narendra Kushwaha v. State of UP* and directions were issued for remedial action and filing of status report by several orders.

3. The matter was last considered on 25.01.2022 wherein reference was also made to the orders passed in OA No. 380/18, *Park Avenue Plot Holders Welfare Society & Anr. v. Union of India & Ors.* and OA No. 999/2019, *Dr. Ajay Kumar v. Union of India & Ors.*, in respect of similar problem at Meerut and order issued by State Government on 19.02.2020, directing prevention of illegal constructions against permitted land user in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. Reference was also made to the order of the Tribunal dated 28.05.2021 in OA No. 114/2021, *Narendra Kushwaha* (Supra). The Tribunal considered the report filed by the District Magistrate, Jhansi dated 22.10.2021 mentioning the steps taken for removing the encroachment and prevention of pollution. Further reference was made to the report of the Additional Chief Secretary dated 21.01.2022 based on the information given by the District Administration. It was held that violations continued in spite of

orders of this Tribunal which called for further remediation. Some extracts from the said order are reproduced below:-

> *"16. Further we find that none of the said reports can be said to comply Tribunal's order in entirety. No report refers to District Environment Plan for which there was a specific direction. Reports also withhold information like quantity of sewage entering Laxmi Tal, water quality data, time for completion of TTP, action plan, if any, for desiltation and cleaning of water etc.*
>
> *17. Maintenance of water body is prime responsibility of statutory authorities as well as statutory regulators under Environmental Laws and other enactments dealing with public health and similar issues. Similarly, a land reserved for green belt/park in the Master Plan whether belongs to State or private owners cannot be allowed to be used for raising any construction. With respect to the area reserved for 'green belt/park', it has been repeatedly held by Supreme Court that such spaces cannot be changed to residential or commercial one.*
>
> *21. Despite the law of land referred above and the orders passed by Tribunal expressing similar views, we find that approach of concerned authorities is very casual, lackadaisical and non-serious. We do not find any element of commitment, sincerity, honest intention and will on the part of authorities in taking effective steps for preservation and protection of green belt/land reserved for park in Master Plan.*
>
> *23.* ***In the above backdrop of the facts, we find it appropriate to have an affirmation of factual report from a Committee comprising of different authorities and, therefore, we constitute a joint Committee comprising of MoEF&CC, CPCB, Department of Agriculture, UP, Department of Forest & Environment, UP and Divisional Commissioner, Jhansi, shall make spot inspection, examine relevant records and submit a factual report within two months. CPCB and Divisional Commissioner, Jhansi will be the nodal agency for coordination and compliance. First meeting of Committee shall be held within 15 days.***
>
> ***24. On the next day of hearing, Municipal Commissioner, Jhansi; Vice Chairman, Jhansi Development Authority; District Magistrate, Jhansi; Divisional Commissioner, Jhansi and Additional Chief Secretary, Urban Development, UP, shall also remain present in virtual mode."***

4. In pursuance of above, Principal Secretary, UD, UP, Municipal Commissioner, Jhansi, Vice Chairman, Jhansi Development Authority and DM Jhansi are present in person. A report has been filed on 12.09.2022 by the Commissioner, Jhansi Division. The report mentions the steps taken to prevent pollution and to protect the water body i.e. Jhansi *Tal*. It is

stated that the water quality is not fit for bathing and thus, is of poor quality. Learned Principal Secretary, UD, UP, assures the Tribunal that by taking remedial action, the situation of pollution will be brought under control soon. With regard to encroachments, it is mentioned in the report of the Commissioner that action has been taken in some cases but there is a stay by the High Court in some matters out of those in which orders have been passed. Further, there is apprehension that taking action against encroachers may adversely affect law and order situation. It has also been observed that several beautification and catchment improvement works are underway and these need to be completed without further delay.

5. However, learned Principal Secretary, UD, UP, submits that upholding the law by removing the encroachment will in fact improve the law and order. We are of the view that the Rule of Law has to be upheld and it is absurd to say that if lawful action is taken law and order situation will deteriorate which means illegality should be tolerated and lawlessness allowed. It is responsibility of the State to protect Water bodies by way of completely stopping entry of sewage into the *Tal* which are significant for environment. The State is to act as trustee and not whimsically as thought by the Commissioner in taking an untenable plea to defeat the law. There is no question of deterioration of law and order in doing so.

6. In this view of the matter, we record the assurance of learned Principal Secretary, UD, UP that further remedial action will be taken for protection of water body by controlling the pollution and removing the encroachments, following due process of law. It appears that against 26 MLD of STPs only 8-10 MLD is treated which needs to be looked into and remedied. In absence of recharging source for the *Tal*, treated sewage

compliant with BOD and Fecal Coliform level may be used for filling the *Tal* and growing fisheries into it.

The Applications will stand disposed of.

A copy of this order be forwarded to the Principle Secretary, UD, UP, by email for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

September 14, 2022
Original Application No. 165/2021
With Execution Application No. 02/2022
IN Original Application No. 114/2021
(I.A. No. 164/2022)
AB

Item No. 01 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Review Application No. 33/2022
In
Execution Application No. 02/2022
In
Original Application No. 114/2021

Narendra Kushwaha Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent

Date of hearing: 10.10.2022

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

IN CHAMBER BY CIRCULATION

ORDER

1. This Application seeks review of order of this Tribunal dated 14.09.2022 in O.A No. 165/2021, *Girja Shankar Rai & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Ors*. In fact, the grievance in the application is confined to seeking clarification that directions to remove encroachments are not confined to buffer zone of lake but also cover the area shown as park in the master plan.

2. Para 1 of the order shows that grievance about encroachments in park as per Jhansi Master Plan 2021 is mentioned. In operative part of the directions, while directing removing encroachments, park is not specifically

mentioned. Consistent with the tenor of the order, direction has to cover encroachments of the park also. We clarify accordingly.

The Review Application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to the Principle Secretary, U.D, U.P, Commissioner, Jhansi, Vice Chairman, Jhansi Development Authority and DM, Jhansi by email for compliance.

If any grievance survives, it will be open to the aggrieved party to take remedies afresh in accordance with law.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

October 10, 2022
Review Application No. 33/2022
In Execution Application No. 02/2022
In Original Application No. 114/2021
AB

Item No. 01 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(Through Video Conferencing)

Execution Application No. 38/2022
IN
Original Application No. 165/2021

Girja Shankar Rai & Ors. Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent

Narendra Kushwaha .... Applicant in E.A. 38/2022

Date of hearing: 14.12.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Narendra Kushwaha, Applicant in Person in E.A 38/2022

ORDER

1. This execution application has been filed for implementing order of this Tribunal dated 14.09.2022 passed in OA No. 165/2021, *Girja Shankar Rai & Ors. vs. State of Uttar Pradesh & Ors.* and EA No. 02/2022 in OA No. 114/2021, *Narendra Kushwaha vs. State of Uttar Pradesh* read with order dated 10.10.2022 passed in Review Application No. 33/2022 in EA No. 02/2022 in OA No. 114/2021, *Narendra Kushwaha vs. State of Uttar Pradesh* alleging that no efforts are being made by the authorities for restoration of Nagar Park, Jhansi which was shown as such in Jhansi Master Plans 2001 and 2021, despite orders passed by this Tribunal.

2. By order dated 14.9.2022, original application was disposed of which was in respect of unauthorized encroachments and pollution in *Laxmi Tal* as also Nagar Park at Jhansi. Principal Secretary, Urban Development, UP himself appeared and assured that illegal encroachments shall be removed, whereafter, original application was finally disposed of. Operative part of order in para 5 and 6 reads as under:

> *"5. However, learned Principal Secretary, UD, UP, submits that upholding the law by removing the encroachment will in fact improve the law and order. We are of the view that the Rule of Law has to be upheld and it is absurd to say that if lawful action is taken law and order situation will deteriorate which means illegality should be tolerated and lawlessness allowed. It is responsibility of the State to protect Water bodies by way of completely stopping entry of sewage into the Tal which are significant for environment. The State is to act as trustee and not whimsically as thought by the Commissioner in taking an untenable plea to defeat the law. There is no question of deterioration of law and order in doing so.*
>
> *6. In this view of the matter, we record the assurance of learned Principal Secretary, UD, UP that further remedial action will be taken for protection of water body by controlling the pollution and removing the encroachments, following due process of law. It appears that against 26 MLD of STPs only 8-10 MLD is treated which needs to be looked into and remedied. In absence of recharging source for the Tal, treated sewage compliant with BOD and Fecal Coliform level may be used for filling the Tal and growing fisheries into it."*

3. With regard to Nagar Park, there was some confusion, hence Review Application No. 33/2022 was filed which was disposed of by order dated 10.10.2022 which reads as under:

> *"1. This Application seeks review of order of this Tribunal dated 14.09.2022 in O.A No. 165/2021, Girja Shankar Rai & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Ors. In fact, the grievance in the application is confined to seeking clarification that directions to remove encroachments are not confined to buffer zone of lake but also cover the area shown as park in the master plan.*
>
> *2. Para 1 of the order shows that grievance about encroachments in park as per Jhansi Master Plan 2021 is mentioned. In operative part of the directions, while directing removing encroachments, park is not specifically mentioned.* ***Consistent with the tenor of the***

order, direction has to cover encroachments of the park also. We clarify accordingly.

The Review Application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to the Principle Secretary, U.D, U.P, Commissioner, Jhansi, Vice Chairman, Jhansi Development Authority and DM, Jhansi by email for compliance.

If any grievance survives, it will be open to the aggrieved party to take remedies afresh in accordance with law."

4. The applicant has stated in this execution application that a large number of unauthorized constructions on Nagar Park had continued and no action has been taken or is being taken, by authorities, till date. This is a serious matter. Responsible authorities must be aware that non-compliance of order of this Tribunal is an offence under Section 26 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') and the order of this Tribunal being at par with decree of Civil Court under Section 25 of the said Act, executable in terms of Section 51 of CPC, which can include procedure of civil imprisonment of the authorities who are violating the order and not executing the same.

5. However, in order to have information about ground level situation, we find it appropriate to constitute a Committee headed by an independent authority. Therefore, we constitute a Committee comprising MoEF&CC, State PCB, District Magistrate, Jhansi and SSP, Jhansi to look into the matter. District Magistrate, Jhansi shall be nodal agency for coordination and compliance. The Committee shall submit a factual report giving information about inventory and extent of encroachments on park land and remedial actions taken, if any, by the authorities concerned. The report may inter-alia cover total area of park at its original stage and the area encroached now. Remedial actions in terms of restoration of park to its original entity may also be provided.

6. We also direct Vice Chairman, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi as also Principal Secretary, Urban Development, UP to submit a report as to what action has been taken in this regard and if no action has been taken then to show cause as to why appropriate action may not be taken against them for non-compliance of orders of this Tribunal.

7. The above reports shall be submitted within two months from today by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

8. List for further consideration on 17.02.2023.

9. A copy of this order be forwarded to MoEF&CC, Principal Secretary, Urban Development, UP, State PCB, Vice Chairman, Jhansi Development Authority, District Magistrate, Jhansi and SSP, Jhansi by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

December 14, 2022
Execution Application No. 38/2022
IN Original Application No. 165/2021
DV